RAJYA SABHA

Tuesday, the 29th April, 2008/9 Vaisakha, 1930 (Saka)
The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*501. [The questioner (SHRI RAHUL BAJAJ) was absent. For answer *vide* page 20]

तेल कंपनियों द्वारा विदेशों में पूंजीगत निवेश

*502. श्री राम जेठमलानी:
श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:††

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तेल कंपनियों द्वारा विदेशों में मूलभूत सुविधाओं के निर्माण में पूंजी निवेश किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक किस-किस कंपनी द्वारा किस-किस देश में कितनी-कितनी पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) इस पूंजी निवेश से कितने प्रतिशत लाभांश का आकलन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिन्शा जे॰ पटेल): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। विदेश में तेल इक्विटी में निवेश के जरिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के प्रयास में तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) अर्थात् आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन-विदेश लिमिटेड (ओवीएल), आयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलम्बिया, क्यूबा, मिश्र, गैबोन, ईरान, इराक, लीबिया, म्यांमार, नाइजीरिया-साओ-प्रिंसीप जेडीजेड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रूस, सूडान, सीरिया, तीमोर और आस्ट्रेलिया, वियतनाम, यमन और वेनेजुएला सहित तेइस देशों में अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) परिसंपत्तियां अर्जित की हैं। उपर्युक्त निवेशों में से वियतनाम, सूडान, रूस, सीरिया और कोलम्बिया में छ: परियोजनाओं में उत्पादन पहले ही शुरु हो चुका है।

जहां तक पूंजीगत निवेशों के लिए प्रस्ताव का संबंध है, तेल सीपीएसयूज अपने प्रस्तावित निवेशों के संबंध में विदेशी कंपनियों/देशों के साथ गोपनीयता करार करती है। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। सामान्यतया तेल सीपीएसयूज यह सुनिश्चित करती है कि उनके निवेश 10% से अधिक की आंतरिक प्रतिफल की दर (आईआरआर) देते हैं।

---

†† सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा द्वारा पूछा गया।

Capital investment by Oil companies in foreign countries

†*502. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:††

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government oil companies are making capital investment in construction of basic facilities in other countries;

(b) if so, the names of such companies whose proposals to make capital investment in different countries are under consideration till now, the details of amount involved and the names of such countries; and

(c) the estimated percentage of profit from this capital investment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DINSHA J. PATEL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. In an effort for securing Energy Security through investment in oil equity abroad, Oil Sector Public Sector Undertakings (PSUs) *viz.*, Oil & Natural Gas Corporation-Videsh Limited (OVL), Oil India Limited, Indian Oil Corporation Ltd., Bharat Petroleum Corporation Ltd., Gas Authority of India Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited have acquired exploration and production (E&P) assets in twenty three countries including Australia, Brazil, Colombia, Cuba, Egypt, Gabon, Iran, Iraq, Libya, Myanmar, Nigeria-Sao-Principe JDA, Nigeria, Oman, Qatar, Russia, Sudan, Syria, Timor & Australia Vietnam, Yemen and Venezuela. Out of the above investments, production has already started in six projects in Vietnam, Sudan, Russia, Syria and Colombia.

As regards proposals for capital investments, Oil CPSUs enter into confidentiality agreement with foreign companies/countries regarding their proposed investments; consideration of such proposals is continuous process. Generally Oil CPSUs ensure that their investments give an internal Rate of Return (IRR) of more than 10%.

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से इन्फॉर्मेशन चाहूंगा कि देश में मूलभूत सुविधाओं के निर्माण की बहुत जरुरत है, क्योंकि इन्हीं के बेसिज़ पर विकास हो पाता है। देश की सरकारी तेल कंपनियां इन सुविधाओं के निर्माण के लिए विदेशों में धन लगा रही है। एक प्रकार से देश में भी बेसिक फैसिलिटीज़ के निर्माण के लिए विकास की जरुरत है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में इन फैसिलिटीज़ के निर्माण के लिए धन लगाने में और विदेशों में इन फैसिलिटीज़ के निर्माण के लिए धन लगाने में देश को कितना-कितना आर्थिक लाभ होने का अनुमान लगाया गया है।

श्री दिन्शा जे. पटेल: चेयरमैन सर, 2006-07 के दौरान देश में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन करीब 31.5 MMT था, जबकि खपत 120.74 MMT थी, अत: उसको बढ़ाने के लिए ओवीएल के जरिए विदेशों में काम करना भी जरुरी है। इसी वजह से विदेश में 31,140 करोड़ की लागत से हमें आगे काम करना है। ओआईएल द्वारा इस काम के लिए 259.51 करोड़ की लागत लगाई गई है।

माननीय सदस्य ने जो पूछा है, रशिया में करीब 14,000 करोड़ की लागत से साखालिन क्षेत्र में काम चल रहा है, साथ ही अन्य करीब 20 देशों में भी हमारा कार्य चल रहा है। अभी तक जो लागत लगाई गई है, उससे हमें करीब 28.14 मिलियन मिट्रिक टन क्रूड ऑयल प्राप्त हुआ है, जिससे देश को करीब 40,000 करोड़ रुपया मिला है। हर साल वहां से हमें 8.76 MMT क्रूड ऑयल प्राप्त होता है, साथ ही इसे और अधिक बढ़ाए जाने के लिए भी कोशिश की जा रही है।

† Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

इस संबंध में मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई पहल और प्रयासों के संबंध में बताना चाहूंगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवरा जी ने कजाखिस्तान, रुस, लीबिया, सीरिया, अल्जीरिया, यमन, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, सूडान और वेनेजुअला की यात्रा की है।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सर, आपके माध्यम से मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि सरकार ने ऑयल कंपनीज़ को विदेशों में पूंजी लगाने की जो मंजूरी दी है, उससे पहले क्या सरकार ने हरेक मामले में अध्ययन कर लिया है कि इससे देश को कितनी कम कीमत पर तेल मिलेगा? क्योंकि आज इस चीज़ की जरुरत है कि देश को तेल कम कीमतों पर मिले। इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है, तेल तो मिलता ही है, लेकिन अपने देश के साथ-साथ विदेशों में भी इतनी पूंजी लगाने के बाद अब हम देश में कितनी कम कीमतों पर तेल मुहैया करवा सकते हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री दिन्शा जे. पटेल: सर, मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसा करने की वजह से देश को करीब 40,000 करोड़ रुपया मिला है। जो भी तेल हमें मिलता है, वह देश में नहीं लाया जाता है, क्योंकि अगर हम उसे यहां लाते हैं तो उसमें लागत अधिक पड़ती है और उसकी कीमत कम मिलती हैं। इसलिए यह जहां पर निकलता है, वहीं के वहीं उस गैस और तेल के बिकने से हमें डॉलर में उसका जो प्राइस मिलता है, उस प्राइस से अगर हम उसे यहां पर परचेज़ करें, इससे भी हमें ज्यादा ऑयल मिल सकता है। इसी वजह से मैंने अभी बताया है कि हमें करीब 40,000 करोड़ रुपया मिल चुका है। पिछली दो बार मंगलूर में करीब दो लाख बैरल ऑयल लाया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसमें लागत और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए वह ऑयल वहां के वहां ही बेच दिया जाता है। इससे सरकार को ज्यादा पैसा मिलता है।

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, मंत्री जी अपने धन को विदेश में लगाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस देश में एक कम्पनी के द्वारा हिन्दुस्तान के हजारों नौजवानों को आज भुखमरी के रास्ते पर ला कर खड़ा कर दिया गया है। लोग अपनी जमीन बेच कर, कर्जा लेकर, बैंकों से कर्जा लेकर, अपनी सारी सम्पत्ति गिरवी रख कर उन्होंने एक ऑयल कम्पनी के रिटेल शाप्स खोले। एक-एक रिटेल शॉप को खोलने में उनके 2 करोड़-3 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब वह कम्पनी पिछले दो सालों से इसलिए तेल नहीं बेच पा रही है, क्योंकि उसकी कीमत और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कीमत में 9-10 रुपए का फर्क हो गया है। नतीजा यह हो रहा है कि वे नौजवान लड़के या तो भूखे मर रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ किसानों की आत्महत्या के बारे में सुन रहे थे, अब इस तरह के कामों से ये बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का कोई दायित्व ऐसे मसले में होगा या नहीं होगा या सरकार खामोशी से इन चीजों को देखती रहेगी? इसी देश की एक कम्पनी इस देश के नौजवानों को लूट रही है और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। जब वे लोग जाते हैं, तो उनकी मार-पिटाई होती है।...(**व्यवधान**)... मुम्बई की पुलिस के द्वारा उन्हें पीटा जाता है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह: मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप इसमें कोई हस्तक्षेप करके उन नौजवानों के जीवन को बचाने का कोई रास्ता ढूंढेंगे या नहीं?

श्री दिन्शा जे. पटेल: माननीय चेयरमैन सर, यह एक प्राइवेट कम्पनी की बात कर रहे हैं। मैं यह भी मानता हूं कि 1998 में गवर्नमेंट ने तय किया कि कोई भी प्राइवेट कम्पनी या किसी को भी रिफाइनरी का काम करना है तो वह कर सकता है उसमें छूट दी गई थी। कोई भी, अगर उसकी Viability ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt...(*Interruptions*)... Please do not interrupt...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह: मैं रिफाइनरी की बात नहीं कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)....

श्री दिन्शा जे. पटेल: मेरा उत्तर तो सुनिए ...(**व्यवधान**)....

MR. CHAIRMAN: Let the Minister reply ...(*Interruptions*)...

श्री दिन्शा जे॰ पटेल: सर, viability होगी या नहीं–यह कम्पनी को चलाने वाले को सोचने की जरुरत है कि यह viable होगा या नहीं होगा, मगर ...(**व्यवधान**)....

श्री शाहिद सिद्दीकी: सर, ...(**व्यवधान**).... यह Misinform कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)....

MR. CHAIRMAN: Please allow the Question Hour to proceed ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादव: सभापति जी, आपसे मेरी विनती यह है कि माननीय सदस्य ने यहां बहुत साफ बात रखी कि जिस तरह से पेट्रोल पम्प के नाम पर पूरे देश भर के लोगों को जो लूटने का काम किया गया या बर्बाद करने का काम किया गया या नहीं किया गया, तो सरकार किस काम के लिए है? मंत्री जी को यह बताने की जरुरत है ...(**व्यवधान**).... सभापति जी, आप प्रोटेक्ट करिए कि मंत्री जी यह बताएं कि वह इस मामले में क्या कार्रवाई करने वाले हैं और वह क्या रास्ता पकड़ेंगे, जिससे कि इस तरह का काम न हो सके। आपसे यह पूछा गया है।

श्री दिन्शा जे. पटेल: सर, मैंने पहले बताया है कि यह प्राइवेट है। वैसे तो यह इस प्रश्न के साथ relevant भी नहीं है ...(**व्यवधान**).... और मैं relevant प्रश्न का तो जवाब दे रहा हूं ...(**व्यवधान**)....

श्री दिग्विजय सिंह: उसका जवाब कौन देगा ...(**व्यवधान**)....

श्री दिन्शा जे. पटेल: यह इस प्रश्न के साथ relevant भी नहीं है ...(**व्यवधान**)....

श्री दिग्विजय सिंह: उसका जवाब कौन देगा ...(**व्यवधान**)....

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt...(*Interruptions*)...

श्री दिन्शा जे. पटेल: मैंने बताया है कि 1998 में ...(**व्यवधान**)....

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, the hon. Minister's reply seems to be "beating about the bush" ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Just one minute...(*Interruptions*)... Please don't interrupt...(*Interruptions*)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, ...(**व्यवधान**)... और प्राइवेट कम्पनी के लिए ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Shri Tapan Kumar Sen. ...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह: सर, हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं ...(**व्यवधान**)... अगर इस सवाल का जवाब पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं देगा, तो कौन मिनिस्टर देगा, हम यह जानना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... Sir, I want your protection. ...(*Interruptions*)... Sir, I want your protection. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let me explain the position...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAY SINGH: Who will answer my question ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. Let me explain the position....(*Interruptions*)...

श्री बनवारी लाल कंछल: सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप जरा मेरी बात सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)... Please, do not interrupt ...(*Interruptions*)... आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)...

श्री बनवारी लाल कंछल: अगर रिलायंस जैसी कोई बड़ी कम्पनी ...(**व्यवधान**)... नौजवानों को लूटने का काम करती है, तो यह सरकार ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. ...(*Interruptions*)... The Chair wants to say something on this ...(*Interruptions*)...

श्री बनवारी लाल कंछल: इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप जरा चुप रहिए ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिए ...(व्यवधान)... The question that has been raised is that a particular commercial company or organisation...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Not a particular company, Sir.

MR. CHAIRMAN: Please, no names have been taken and no names will be taken till it is there in the question.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is not a particular company, Sir.

MR. CHAIRMAN: Just a minute. Mr. Ahluwalia, we all understand that. The company is charging more than the accepted price. As a result of which, it is losing money and unable to pay to its employees who are in distress. Now, that is the question. The distressed. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAY SINGH: No, Sir. ...(*Interruptions*)... All retail outlets of that company are closed. That company is not doing business now. All retail outlets of that particular company are closed today. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Just one minute. ...(*Interruptions*)... Just a minute please. ...(*Interruptions*)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: वह आप कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Panyji, please sit down. Let me tell you what happens in similar cases in other aspects of business activity. Surely, there must be a normal law to deal with these questions. Now, can we go to the next supplementary please. ...(*Interruptions*)... Shri Balbir Punj. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAY SINGH: If the hon. Minister is not able to reply to my question, who will reply? ...(*Interruptions*)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: He is helping that particular company. That is the problem. ..(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Will you please settle down? ...(*Interruptions*)... Will you please settle down? ...(*Interruptions*)...

SHRI VIRENDRA BHATIA: Sir, please allow me to put one question. ...(*Interruptions*)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, this is abdication of responsibility. ...(*Interruptions*)...

SHRI VIRENDRA BHATIA: Sir, please allow me to put one question. ...(*Interruptions*)...

MR CHAIRMAN: No, it is not your turn to put the question. ...(*Interruptions*)... No; no questions. Till your turn comes you will not get it. ...(*Interruptions*)...

SHRI VIRENDRA BHATIA: Sir, I have raised my hand. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You cannot interfere like this. ...(*Interruptions*)... I am sorry. ...(*Interruptions*)... If you have raised your hand, your turn will come. ...(*Interruptions*)...

SHRI VIRENDRA BHATIA: Sir, every time I am deprived of putting question. ...(*Interruptions*)... I do not pass any remarks against the Chair, but every time I am deprived of putting question. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Mr. Virendra Bhatia, there is an established procedure for putting supplementaries. You have raised your hand. Your name has been noted down. Your name will be called. Why are you anticipating that your name will not be called and interrupting the pronounce? ...(*Interruptions*)... I am afraid, it is not so. ...(*Interruptions*)... I am willing to share with the hon. Members of this House the process by which supplementaries are taken on call. Anybody is free to have a look at it, or, can consult the Secretary-General on it. Can we, now, please proceed with the supplementaries? ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAY SINGH: No, Sir. First, let the hon. Minister answer my question. If he is not able to answer, who will answer my question? ...(*Interruptions*)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, it is such an important question that it affects thousands of people. ..(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Nobody is being heard here. ...(*Interruptions*)...

DR. MULRI MANOHAR JOSHI: He cannot circumvent the solution. ...(*Interruptions*)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, यह सदन जनता के हितों के संरक्षण के लिए है, कॉर्पोरेट कंपनियों के हितों के संरक्षण के लिए नहीं है ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Is it the intention of the hon. Members that no questions be put? ...(*Interruptions*)... देखिए, आप बोल सकते हैं, अगर दूसरे न बोलें।...(व्यवधान)... If ten people speak at a time nobody can be heard.

श्री शरद यादव: सर, मुझे विनती करनी है कि सरकार सक्षम है और जो सवाल पूछा गया है, उसके साथ हजारों लोगों का संबंध है। सिर्फ उन से इतना ही पूछना है कि इस मामले में वह क्या करेंगे? मंत्री जी से मेरी विनती है कि आप कह सकते हैं कि इस मामले में कोई-न-कोई रास्ता आप निकालेंगे। सर, यही एक क्वैश्चन था जिस के चलते आप को प्रोटैक्ट करना चाहिए। सर, यहां मंत्री जी, सरकार Almighty होती है और उसे सब अधिकार इसीलिए मिले हुए हैं और यह सदन इसीलिए है। इसीलिए मंत्री जी इस में साफ-साफ कहें कि इसमें वह क्या करेंगे?

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: How can he abdicate his responsibility?

MR. CHAIRMAN: Will you please settle down?

डॉ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में जब भी कभी सवाल उठते हैं, बड़े गंभीर सवाल उठते हैं, हजारों आदमी उससे जुड़े हुए होते हैं। सरकार का रुख हमेशा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, मामले को निबटाने का होना चाहिए, एक बिल्कुल compassionate response आना चाहिए, मगर वहां से कोई जवाब आता नहीं। आपसे भी यह दरख्वास्त है कि आप ऐसे मामले में उनको कुछ हिदायत तो दें कि वे जवाब दें। आज नहीं दे सकते, तो कल दें।...(व्यवधान)...

श्री सदय प्रताप सिंह: आप सबको अलाऊ कर रहे हैं तो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, दूसरों का नम्बर नहीं आएगा, अगर आप यह डिबेट शुरू करेंगे।...(व्यवधान)... If you want the Question Hour to proceed and supplementaries be asked, then, please don't raise wider questions. ...(*Interruptions*)... No; no. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादव: सर, मंत्री जी खड़े हुए हैं, वे बता रहे हैं।...(व्यवधान)... सर, मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: You are not allowing him to reply.

श्री दिन्शा जे॰ पटेल: सर, मेरे सीनियर साथी और सदस्य बोल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि 1998 में जो तय किया गया, उस वजह से कोई भी व्यक्ति कहीं भी, ऑयल के बारे में कुछ भी काम कर सकता है, रिफाइनरी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री शाहिद सिद्दीकी: लूट भी सकता है? ...(**व्यवधान**)...

†[شری شاہد صدیقی : لوٹ بھی سکتا ہے؟ ۔مداخلت۔]

श्री दिन्शा जे॰ पटेल: सुनिए तो सही। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't interfere, Mr. Shahid Siddiqui. ...(*Interruptions*)...

श्री दिन्शा जे॰ पटेल: आप सुनते नहीं हैं, फिर बात करते हैं।

श्री शाहिद सिद्दीकी: सुनाइए आप।

†[شری شاہد صدیقی : سنائیے آپ۔]

श्री दिन्शा जे॰ पटेल: आप सुनो तो हम सुनाते हैं आपको।

श्री शाहिद सिद्दीकी: आप वहीं बात ...(**व्यवधान**)

†[شری شاہد صدیقی : آپ وہی بات ۔مداخلت۔]

MR. CHAIRMAN: Mr. Shahid Siddiqui, please sit down. ...(*Interruptions*)... Please go ahead, Mr. Minister. ...(*Interruptions*)...

श्री दिन्शा जे॰ पटेल: तो कोई भी व्यक्ति उसकी वॉयब्लिटी के अनुसार यह करता है। यह प्राइवेट कम्पनी की प्रॉब्लम है। मैंने यह भी कहा कि उसके लिए अलग से नोटिस दिया जाएगा, पूछा जाएगा, उसके बारे में तलाश करके उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा।

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Chairman, Sir, the Government is looking for opportunoties to invest in oil abroad because of oil security. Sir, the oil companies in India, particularly, the public sector companies are suffering heavy losses on account of increase in crude oil prices abroad. So, I want to know from the hon. Minister as to what are the losses suffered by the PSUs which are investing abroad. Secondly, what are the duties which the Central Government imposes on crude oil? What has been the income of the Central Government from these duties in the last four years? Mr. Chairman, Sir, what is happening is that the crude oil prices are rising and the Government is using the additional revenue coming from there to fill up its fiscal deficit. It is, virtually, trading and profiteering on the misery of the people.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, I have put two questions.

श्री दिन्शा जे॰ पटेल: माननीय सभपति महोदय, माननीय सदस्य जी जो बता रहे हैं, उसमें कम्पनी और गवर्नमेंट लाभ उठा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन, कम्पनियां अगर घाटे में हों, तो गवर्नमेंट बांड्स के जरिए उनको हेल्प करती है और उसमें कैसा रास्ता निकाला जाए, संबंधित मंत्रालय के साथ भी इस बारे में बातचीत करती है। मगर, यू.पी.ए. सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक कैरोसीन और LPG में आज तक एक रुपया भी नहीं बढ़ाया है और सारे एशिया में 9.5 पैसे में, सस्ते से सस्ता कैरोसीन PDS के माध्यम से गरीब लोगों को दिया जाता है और LPG में भी एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: There should be no cross talk please. ...(*Interruptions*)...

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

श्री बलबीर पुंज: दोनों में प्राइस ...(**व्यवधान**)...

श्री दिनशा जे॰ पटेल: सुनिए तो सही। LPG में एक सिलेंडर पर करीब 303 रुपए का घाटा है, केरोसीन में 24 रुपए का घाटा है और पेट्रोल-डीजल में भी घाटा उठाकर हम यह काम कर रहे हैं। यहां पर, हमारे देश में ज्यादातर उत्पादन कम है, उसको ढूंढने के लिए भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। 162 ब्लॉक ढूंढ लिए गए हैं और दिए गए हैं, उनमें से ज्यादा उत्पादन कैसे हो सके, यह देखा जा रहा है। मैंने पहले भी बताया कि यहां 120 मिलियन मीट्रिक टन की जरूरत है, मगर यहां 31-32 मिलियन मीट्रिक टन तेल पैदा होता है। हम 149 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल यहां मंगवाते हैं, उसको भी रिफाइनरीज में प्रोसेस करके, उसका घाटा कम करने के लिए हम पैट्रोल को बाहर भेजते हैं और करीब 81,000 करोड़ रुपया उससे हमने वापिस भी लिया है। इस तरह घाटा कम करने के लिए भी कोशिश हो रही है, हम मुनाफा नहीं कर रहे हैं...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please do not ask. ...(*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, he has not answered my question. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please do not ask supplementaries on supplementaries.

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, just one minute. I am just reiterating my original question. My original question was, what is the amount of duty which the Central Government has collected on imported crude in the last four years, the year-wise figures. That is my question. You haven't answered that question. आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The question is very specific. If the data is available with the hon. Minister, he can give it, Otherwise, it can be given to the Member later. ...(*Interruptions*)...

श्री दिनशा जे॰ पटेल: जहां तक शुल्क की बात है, यदि आप संबंधित मंत्री से पूछ लें, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा ...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर पुंज: क्या आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि पिछले 4 सालों में केन्द्रीय सरकार ने कितना ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Balbir Punj, this thing is over. ...(*Interruptions*)... Please, Shri Virendra Bhatia.

SHRI VIRENDRA BHATIA: Sir, the Minister has just told that he has no control over a private company. May I ask one question to the Minister? The company, on the basis of some representation and inducement, represented something...

MR. CHAIRMAN: Be careful with the words you are using.

SHRI VIRENDRA BHATIA: Pardon please.

MR. CHAIRMAN: Be careful with the words you are using.

SHRI VIRENDRA BHATIA: Sir, I am asking about a company which made the advertisement, induced certain persons, represented certain persons that it will give profit. The persons invested a huge amount of money. Now, they are closing it, means thereby that they have misrepresented to the persons who have invested the money. This act induced them to invest the money. This amounts to ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: What is the supplementary question?

SHRI VIRENDRA BHATIA: Sir, please listen to my question. This amounts to cheating and is an offence under Section 420. ...(*Interruptions*)... They may not have a direct control

on the company, but, on the same subject, they can lodge the FIR against such companies and the responsible Directors of those companies. ...(*Interruptions*)... My question is, whether the Government is willing to lodge an FIR and take criminal action against them. ...(*Interruptions*)...

श्री दिनशा जे॰ पटेल: सभापति जी, मैंने पहले ही कहा है कि यह प्रश्न, इस सवाल से संबंधित नहीं है, तो भी इसके लिए कोई भी complaint भेजी जाएगी, तो उसके खिलाफ तलाशी करके क्या हो सकता है, यह करने की कोशिश हमारी सरकार और हमारा डिपार्टमेंट जरूर करेगा।

माननीय सदस्य: आप तलाशी करते-करते खो जाओगे ...(**व्यवधान**)...

Buddhist heritage centre in Orissa

*503. SHRI RUDRA NARAYAN PANY:††
SHRI B.J. PANDA:

Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government of Sri Lanka has asked its Indian counterpart to develop Buddhist sites in the Southern sector, *i.e.* Andhra Pradesh and Orissa, to facilitate Buddhist tourists to visit such heritage centres;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the action plan of Government to develop such Buddhist heritage centres in Orissa to promote Buddhist tourism in that State?

†THE MINISTER OF TOURISM (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Ministry of Tourism extends Central Financial Assistance, under the centrally sponsored scheme of Product/Infrastructure Development for Destinations and Circuits to the State Governments/Union Territories for tourism projects identified and prioritized in consultation with them for the improvement of infrastructure at important tourism destinations and circuits. Ministry of Tourism has sanctioned Rs. 740.66 Lakh, for the Development of facilities at Lalitgiri, Ratnagiri, Udaigiri and Langudi Circuit in Orissa. In addition to the above, Rs. 488.51 Lakh, was also sanctioned for the Development of Peace Park and Amphitheatre at Dhauli in Orissa.

Ministry of Tourism promotes diverse tourism products of India including Buddhist sites in Orissa through its Media Campaigns, Website, Production and Distribution of Publicity material and dissemination of information through India Tourism Offices in India and abroad.

श्री रूद्रनारायण पाणि: सभापति जी, भले ही हमारे गरीब राज्य उड़ीसा के साथ हर मामले में भेदभाव होता है, लेकिन दुनिया में शांति स्थापना करने में उड़ीसा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उड़ीसा की पावन धरती पर "चंडाशोक", "धर्मा

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri **Rudra Narayan Pany**.